Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 7.384
Volume - 8, Issue - 7, July - 2025

DOIs:10.2018/SS/202507008 --:-- Research Paper / Article / Review

आरएसएस और ग्रामीण समाज: सामाजिक संरचना में परिवर्तन की समाजशास्त्रीय पड़ताल

[1] ओकेश , [2] अनुज यादव
[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
[2]शोधार्थी, हिन्दी विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय
ईमेल - 1. mr.okay580@gmail.com 2. Anuj230179@cuh.ac.in

सारांश : वर्तमान शोध ग्रामीण भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका और उसके प्रभाव का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आरएसएस, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित संगठन, वर्षों से गांवों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करता आ रहा है। यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि आरएसएस की विचारधारा, संगठनात्मक गतिविधियाँ और सामाजिक पहलों ने ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचना – जैसे जातीय संबंध, वर्ग व्यवस्था, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक गतिशीलता – को किस प्रकार प्रभावित किया है।शोध में गुणात्मक विधियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न ग्रामों में आरएसएस की गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन और साहित्य समीक्षा की गई है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार आरएसएस ग्रामीण भारत में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक जागरूकता और राजनीतिक चेतना को आकार देता है, साथ ही यह भी कि इसके प्रयास किस हद तक सामाजिक विभाजन को समाप्त करने में सफल हुए हैं। यह शोध ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझने हेतु एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ परंपरा और विचारधारा के बीच टकराव एवं समंजन दोनों ही मौजूद हैं।

बीज शब्द : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), ग्रामीण समाज ,सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ।

1. परिचय :

भारत का ग्रामीण समाज एक जटिल सामाजिक संरचना पर आधारित है, जिसमें जाति, वर्ग, धर्म और परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सामाजिक परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाएं प्रारंभ हुईं, जिनमें विभिन्न संगठनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जिसने न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण भारत में भी अपनी गहरी पैठ बनाई है। यह संगठन स्वयं को सांस्कृतिक जागरण का वाहक मानता है, और इसके कार्यक्रमों व विचारधारा का सीधा प्रभाव ग्रामीण समाज के ताने-बाने पर देखा गया है।

ग्रामीण भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है और समय के साथ इसने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वदेशी मॉडल विकसित किया है। आरएसएस की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट पर नजर डालने से पता चलता है कि किस तरह स्थानीय कारकों को ध्यान में रखकर और उसके अनुसार तैयार की गई परियोजनाएं चुपचाप ग्रामीण भारत की सूरत बदल रही हैं। आज जब ग्रामीण भारत राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तेजी से बदल रहा है, यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आरएसएस जैसे संगठन इस बदलाव में क्या भूमिका निभा रहे हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य है: यह विश्लेषण करना कि आरएसएस की गतिविधियाँ ग्रामीण समाज में सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। साथ ही यह समझना का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण समाज में जातीय, वर्गीय और सांस्कृतिक संबंधों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उनका संबंध आरएसएस की उपस्थिति से किस प्रकार है।

इस शोध में **गुणात्मक अनुसंधान पद्धति** का प्रयोग किया गया है।इसके अंतर्गत **दस्तावेज़ीय विश्लेषण** किया गया है। इसके अतिरिक्त साहित्य समीक्षा के माध्यम से आरएसएस के सामाजिक कार्यों और विचारधारा की व्यापक समझ प्राप्त की गई।

2. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण एमिल दुर्खीम और टैल्कोट पारसन्स जैसे समाजशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें समाज को एक संगठित संरचना माना गया है, जहाँ प्रत्येक संस्था (जैसे परिवार, धर्म, संगठन) अपना विशिष्ट कार्य करती है जिससे सामाजिक संतुलन बना रहता है (Parsons, 1951)। आरएसएस को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि यह संगठन ग्रामीण समाज में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक अनुशासन और नैतिक शिक्षा के माध्यम से एक स्थायित्व लाने का प्रयास करता है।

राल्फ डाहरनडॉर्फ द्वारा प्रस्तुत किया गया संघर्ष सिद्धांत यह मानता है , जिसमें समाज को संघर्ष और असमानता से भरा हुआ माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में विभिन्न वर्ग और जातियाँ सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष करती हैं (Dahrendorf, 1959)। आरएसएस के संदर्भ में, यह देखा जा सकता है कि संगठन किस प्रकार ग्रामीण समाज में नए सामाजिक गठबंधन बनाता है, जिससे कभी-कभी पारंपरिक सामाजिक ढाँचे को चुनौती मिलती है और वर्चस्व की नई परिभाषाएं उभरती हैं।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जो राष्ट्र की पहचान को उसकी परंपरा, संस्कृति और इतिहास से जोड़ती है। विनायक दामोदर सावरकर ने "हिंदुत्व" की अवधारणा दी, जिसे आरएसएस ने आगे बढ़ाया (Savarkar, 1923; Jaffrelot, 1996)। ग्रामीण समाज में आरएसएस शाखाओं, संस्कार वर्गों और त्योहारों के आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना का विस्तार करता है, जिससे एक साझा सांस्कृतिक चेतना का निर्माण होता है।

भारत के ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से जातीय पदानुक्रम, वर्ग भेद और सामाजिक गतिहीनता पाई जाती रही है। लेकिन जैसे-जैसे संगठनों की भागीदारी बढ़ी, सामाजिक गतिशीलता की नई संभावनाएँ उभरीं (Srinivas, 1962)। आरएसएस दलितों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और युवाओं को अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित कर ग्रामीण समाज के भीतर नए प्रकार की सामाजिक जागरूकता और गतिशीलता उत्पन्न करता है।

एंटोनियो ग्राम्शी का आधिपत्य सिद्धांत यह बताता है कि सत्ता केवल बल से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सहमति के माध्यम से स्थापित होती है (Gramsci, 1971)। आरएसएस ग्राम स्तर पर अपनी शाखाओं, नैतिक शिक्षा, और राष्ट्रवादी संस्कृति के ज़रिये एक "सांस्कृतिक नेतृत्व" विकसित करता है, जिससे लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित किया जाता है।

उपरोक्त सिद्धांत यह समझने में सहायक हैं कि आरएसएस केवल एक सामाजिक संगठन नहीं है, बल्कि वह ग्रामीण समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे में हस्तक्षेप कर उसे पुनः परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। यह समाजशास्त्रीय फ्रेमवर्क शोध को वैचारिक गहराई प्रदान करता है।

3. आरएसएस: एक परिचय

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 1925 में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में की गई थी। इसका मूल उद्देश्य भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में संगठित करना और हिंदू समाज में व्याप्त विघटनकारी तत्वों को समाप्त कर एक संगठित, आत्मनिर्भर और समरस समाज का निर्माण करना रहा है। आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा अत्यंत अनुशासित और केंद्रीकृत है, जिसमें स्वयंसेवकों की शाखाओं के माध्यम से विचारों और मूल्यों का प्रसार किया जाता है। यह शाखाएँ प्रतिदिन के नियमित कार्यक्रमों, शारीरिक और वैचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयंसेवकों को तैयार करती हैं। संघ ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक सीमित भूमिका निभाई, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसकी गतिविधियाँ तीव्र गति से बढ़ीं। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, किंतु वह शीघ्र ही पुनः सक्रिय हुआ। 1950 और 60 के दशक में संघ ने समाज सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी शुरू की।

आरएसएस की विचारधारा "हिंदू राष्ट्रवाद" (Hindutva) पर आधारित है, जिसमें हिंदू संस्कृति को भारत की मूल पहचान माना जाता है। संघ का दृष्टिकोण यह है कि यदि समाज संगठित होगा, तो राष्ट्र स्वतः सशक्त होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संघ की कार्यप्रणाली मुख्यतः निम्नलिखित माध्यमों से सक्रिय है:

- **शाखाएँ:** जहाँ ग्रामीण स्वयंसेवकों को शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **संस्कार केंद्र:** बच्चों को 'भारतीय संस्कृति' और 'राष्ट्रभक्ति' की शिक्षा दी जाती है।
- **ग्राम संपर्क अभियान:** गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित करना।
- **सेवा परियोजनाएँ:** जैसे शिक्षा केंद्र, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान आदि।

4. भारतीय ग्रामीण समाज

भारत का ग्रामीण समाज एक जटिल, बहुस्तरीय और पारंपरिक सामाजिक ढांचे पर आधारित है, जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में निहित हैं। इस खंड में हम भारतीय ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचना को जाति, वर्ग, लिंग और सामाजिक संबंधों के सन्दर्भ में विश्लेषित करेंगे

भारतीय ग्रामीण समाज, इतिहास में भी और आज भी, एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। भारत में, गाँव हमेशा से ही एक केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं, और ग्रामीण समाज भारतीय संस्कृति और समाज का एक अभिन्न अंग है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्र 60.43 % प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें उपजाऊ मैदान, ऊबड़-खाबड़ पहाड़, घने जंगल और शुष्क रेगिस्तान शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अपना अलग परिदृश्य, प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिस्थितियाँ हैं, जो कृषि पद्धतियों और आजीविका को प्रभावित करती हैं। भारत का ग्रामीण जीवन समुदाय और परस्पर जुड़ाव की भावना से भरा हुआ है। दैनिक जीवन सदियों पुराने रीति-रिवाजों, सामाजिक समारोहों और सांप्रदायिक उत्सवों के इर्द-गिर्द घूमता है जो समुदाय को एक साथ बांधते हैं। भारत के गांव में सांस्कृतिक विरासत गहरी है, जो लोक संगीत, नृत्य, कला और व्यंजनों जैसे विविध रूपों में प्रकट होती है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान का दावा करता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही सदियों पुरानी परंपराओं से समृद्ध है। त्यौहार ग्रामीण कैलेंडर को चिह्नित करते हैं, जीवन को रंग, संगीत और उत्साह से भर देते हैं, फसल से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक सब कुछ मनाते हैं।

कृषि ग्रामीण भारत की रीढ़ है, जहां 158 मिलियन आबादी खेती या उससे संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। दक्षिण के हरे-भरे चावल के खेतों से लेकर उत्तर के सुनहरे गेहूं के खेतों तक, देश के विविध परिदृश्य में विविध फसलें फलती-फूलती है। पारंपरिक खेती के तरीके आधुनिक प्रथाओं के साथ सह-अस्तित्व में हैं, जो प्राचीन ज्ञान और तकनीकी नवाचार के मिश्रण को दर्शाते हैं।

अपनी अनूठी सांस्कृतिक विशेषताओ के करण ग्रामीण समाज प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिसमें कृषि और उससे संबंधित व्यवसाय मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ थीं। किन्तु विभिन अपक्रांतों के करण इसकी सामाजिक संरचना मूल रूप से विचलित हुए जिसके कारण भर्तीय गाँव पिछड़ेपन का शिकार हुए। डॉ अंबेडकर जी ने गाँव को घोर असमानता का छटेर कहा जहा लोकतंर संभावित नहीं है। इसलिए भारत में ग्रामीण क्षेत्र का विकास समावेशी विकास को प्राप्त करने और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ चल रहे परिवर्तनों व रोजगार, शिक्षा, सुविधाओं और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अन्वेषण किया गया है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कारकों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। भारतीय ग्रामीण समाज की पारंपरिक संरचना बहुस्तरीय और विषम रही है, जिसमें जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर सामाजिक असमानता को संस्थागत स्वरूप प्राप्त था। इन पारंपरिक ढांचों ने समाज में स्थायित्व और अनुशासन तो दिया, लेकिन साथ ही सामाजिक गतिशीलता और समानता की संभावनाओं को सीमित भी किया। ऐसे में, जब आरएसएस जैसे संगठन ग्रामीण समाज में प्रवेश करते हैं, तो वे इस पारंपरिक संरचना के साथ किस प्रकार का संवाद और हस्तक्षेप करते हैं, यह शोध का केंद्रीय बिंदु बनता है।

5. आरएसएस का ग्रामीण समाज पर प्रभाव

आरंभ में शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहने वाला आरएसएस 1970 के दशक से गांवों की ओर उन्मुख हुआ। 'ग्राम विकास योजना', 'एकात्म मानववाद', और 'सामाजिक समरसता अभियान' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से संघ ने ग्रामीण समाज में अपनी वैचारिक और संगठनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ग्रामीण भारत में अपने वैचारिक और सामाजिक अभियान के माध्यम से विविध स्तरों पर प्रभाव डाला है। यह प्रभाव केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, जातीय संबंधों, सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक गतिशीलता तक फैला हुआ है। इस खंड में हम इन प्रभावों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

सामाजिक समरसता और जातिगत संबंधों में हस्तक्षेप

आरएसएस ने "सामाजिक समरसता" (Social Harmony) को अपने अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया है। इसके अंतर्गत वह दलित और पिछड़े वर्गों के साथ मेल-जोल बढ़ाने, उनके साथ भोजन करने, पूजा स्थलों में समान भागीदारी की पहल करता है।

हालांकि यह प्रयास जाति भेदभाव को कम करने की दिशा में प्रतीत होता है, कई समाजशास्त्री मानते हैं कि यह समरसता "समानता" की बजाय "सामंजस्य" (Harmony without Equity) की अवधारणा पर आधारित है, जहाँ पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह चुनौती नहीं दी जाती।

वैचारिक प्रसार और सांस्कृतिक चेतना का निर्माण

आरएसएस की शाखाएं और संस्कार केंद्र ग्रामीण युवाओं, बच्चों और महिलाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और "भारतीय संस्कृति" के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। यह वैचारिक प्रशिक्षण उन्हें एक खास प्रकार की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है, जिसे संघ "हिंदू राष्ट्रीयता" के रूप में परिभाषित करता है।

महिलाओं और युवाओं की भागीदारी

आरएसएस की महिला शाखा "राष्ट्र सेविका समिति" और अन्य अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं को भी संगठित किया जाता है। महिलाओं को पारंपरिक भारतीय नारी की भूमिका में प्रशिक्षित करते हुए उन्हें समाज सेवा, सांस्कृतिक आयोजनों और शिक्षा से जोड़ा जाता है।

युवाओं को खेल, देशभक्ति गीतों, और शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता और सामूहिकता की भावना विकसित होती है।

6. सामाजिक सेवाओं के माध्यम से विश्वास निर्माण

आरएसएस और इसके सहयोगी संगठन जैसे सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं के माध्यम से संगठन स्थानीय समाज में अपनी स्वीकार्यता और भरोसे को बढ़ाता है।

यद्यपि आरएसएस से प्रेरित और इसके एक दिग्गज भारत रत्न नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित संगठन दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआई) ने 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चित्रकूट-गोंडा क्षेत्र में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन आरएसएस ने इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लगभग एक दशक पहले अपनाया था।

ग्राम संकुल (ग्राम समूह) परियोजना के तहत, आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा देश भर में ब्लॉक स्तर पर गांवों की पहचान की गई है, जहाँ कई पहल शुरू की गई हैं। ग्रामीणों को कुटीर उद्योग शुरू करने और विशेष रूप से गायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डेयरी फार्मिंग के माध्यम से अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और साथ ही प्रशिक्षित और कुशल बनाया जाता है। जैविक खेती और मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करने और बढ़ाने

पर भी जोर दिया जा रहा है। जल स्रोतों को संरक्षित करने और खेती में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

आरएसएस की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट पर नजर डालने से पता चलता है कि किस तरह स्थानीय कारकों को ध्यान में रखकर और उसके अनुसार तैयार की गई परियोजनाएं चुपचाप ग्रामीण भारत की सूरत बदल रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "रूपाखेड़ी-अंता, सांगोद खंड और तेलंगाना के आदिलाबाद जिले और कर्नाटक के पुत्तूर जिले के सभी गांवों में गहन काम चल रहा है। यह काम 5,000 से ज़्यादा गांवों तक पहुँच चुका है। संकुल योजना के तहत 15 संकुलों के 310 गांवों में स्वावलंबन उन्मुखी कार्यक्रम चलाए गए हैं। पतरातू (झारखंड) में सिलाई कक्षाओं में भाग लेने के बाद आज 400 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। भुज में 9 गांवों में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि पर गोबर आधारित जैविक खेती की जा रही है। दक्षिण कर्नाटक के करीब 800 गांवों में आरएसएस से प्रेरित संगठन लोकसेवा प्रतिष्ठान के निर्देश पर ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। आरएसएस से प्रेरित एक अन्य संगठन गंगा सेवा 9 राज्यों के 22 गांवों में 37 स्वावलंबन केंद्र चलाता है । उत्तराखंड में उत्थान परिषद प्रवासी पंचायत सहित विभिन्न कार्यक्रम चला रही है।

2021-22 में आरएसएस द्वारा चलाए गए सबसे प्रभावशाली अभियानों में से एक भूमि की गुणवत्ता में सुधार करना था। इसे भूमि सुपोषण अभियान नाम दिया गया और इसे अक्षय कृषि परिवार नामक एक मंच के माध्यम से चलाया गया । आरएसएस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भूमि सुपोषण अभियान में 18,694 गांवों के 5,41,968 किसानों ने भाग लिया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आरएसएस से बाहर के कई संगठनों ने भी हाथ मिलाया। इन संगठनों में कनेरी मठ, गायत्री परिवार, पतंजलि योग प्रतिष्ठान, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन शामिल थे।

आरएसएस ने वर्ष 2023-24 की अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है, "ग्राम संकुल स्वावलंबन परियोजना के तहत, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से, 10-15 गांवों के समूहों में कम बजट वाली, समाज-उन्मुख परियोजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को रोजगार प्रदान किया गया है। यह एक दशक से चल रहा है। अचार बनाने, सिलाई, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम का प्रशिक्षण, लघु उद्यम, बांस की खेती, इससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण और बिक्री जैसे काम क्लस्टरों में किए जा रहे हैं।"

संयोग से, केंद्र ने इन पहलों से प्रेरणा ली है। एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र ने सितंबर, 2017 में “पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना” शुरू की थी। इस परियोजना का शुभारंभ तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किया था।

सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह परियोजना एक प्रयोग है तथा उत्तराखंड में क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास के लिए उपयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को तैयार करने और कार्यान्वित करने का एक प्रयास है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी और नानाजी देशमुख जैसे आरएसएस के दिग्गजों ने 1960 के दशक से ही बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीण विकास का पश्चिमी मॉडल भारतीय गांवों के लिए संभव नहीं है। ग्रामीणों के लिए आय के कई स्रोत विकसित करना महत्वपूर्ण है। स्थानीय प्रतिभाओं और क्षेत्र विशेष कौशल को बढ़ावा देना और उनका विपणन करना भी महत्वपूर्ण है।

आर.एस.एस. ने शुरू में कुछ पायलट परियोजनाओं के साथ प्रयोग किया और धीरे-धीरे महसूस किया कि भारत की विकास कहानी को स्थायी बनाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ग्रामीण विकास मॉडल का होना ज़रूरी है। भारतीय

किसान संघ के माध्यम से, इसने किसानों के साथ काम करना शुरू किया और चौपाल, डी.आर.आई., सेवा भारती जैसे कई अन्य संगठनों के माध्यम से, इसके स्वयंसेवक माइक्रोफाइनेंस से लेकर हस्तशिल्प तक की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए कई तरह की सेवाएँ प्रदान करते हैं। आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा पिछले अनुभवों से प्राप्त सबसे बड़ी सीखों में से एक, जिसे उन्होंने कई मंचों पर साझा किया है, यह है कि गांव के विकास के लिए एक समान समरूप मॉडल नहीं हो सकता। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएँ होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। यही कारण है कि आरएसएस गांवों के ऐसे समूहों पर काम करता है, जिनकी विशेषताएँ समान होती हैं। इस 'समूह' दृष्टिकोण ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के मामले में जमीनी स्तर पर प्रभावशाली परिणाम दिए हैं।

इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक पांच वर्ष पर किया जाता है, जिसमें ग्राम विकास गतिविधि से जुड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रांतों के ग्राम विकास गतिविधि के संयोजक, सह संयोजक एवं प्रभात ग्राम से जुड़े लोग शामिल होते हैं। सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो तिहाई शाखाएं गांव में और एक तिहाई नगरों में चलती हैं। चूँकि भारत में लगभग 60 प्रतिशत समाज गांव में बसता है। वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण परिवेश के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। इसलिए संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शाखाओं के माध्यम से गांवों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। गांव में समरसता की बड़ी चुनौती है। संचार माध्यमों की उपलब्धता के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में सही और उपयोगी जानकारियों का अभाव है। गांव में सही जानकारी और सही दृष्टिकोण पहुंचाने का प्रयास का प्रयास अपनी शाखाओ के माध्यम से किया जाता है।

7. भारतीय किसान संघ

इसकी स्थापना चार मार्च 1979 में दत्तोपन्त ठेंगडी ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों का समग्र विकास है। किसानों के बीच सभी राज्यों में काम है। पिछले कुछ समय से गांव और किसान अनेक प्रश्नों से जूझ रहे हैं। संघ का विचार है कि किसान को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। किसानों के प्रश्नों को समझकर उनके अनुकूल नीति सरकार को बनानी चाहिए। बैठक में कृषि के संबंध में भी विचार किया गया है। संघ प्रयास करत है कि किसान जैविक खेती की ओर लौटें। संघ ने इस दिशा में कुछ योजना बनाई है। किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। ग्राम विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए संघ 30-35 आयुवर्ग के व्यक्तियों को अपने साथ जोड़कर कार्य कर्ता है।

8. परिवार: समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई

परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संघ ने कुटुंब प्रबोधन का काम अपने हाथ में लिया है। व्यक्ति के निर्माण में उसके परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को संस्कार और जीवनदृष्टि परिवार से मिले तो उनका विकास ठीक प्रकार होता है। परिवार समाज जागरण का केंद्र बनें, इसके लिए संघ के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। संघ कार्य के माध्यम से लगभग 20 लाख परिवारों तक पहुंचा है। एक अनुमान के अनुसार सवा करोड़ लोग संघ के संपर्क में आए हैं। समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए कुटुंब प्रबोधन के कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है।

9. भारतीय मजदूर संघ

23 जुलाई 1955 को भोपाल में दत्तोपन्त ठेंगड़ी द्वारा स्थापित यह देश का सबसे बड़ा केंद्रीय मजदूर संगठन है। इसका नारा है, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। अभी देश के सभी राज्यों में काम है। दो करोड़ के लगभग सदस्य हैं। यह संगठन अधिकार के साथ कर्तव्य की भी बात करता है। भगवा ध्वज को झंडा के रूप में अपनाया है।

10. लघु उद्योग भारती

भारत में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में पंजीकृत है। 1994 में स्थापना हुई। भारतीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त लघु उद्योगों की कठिनाइयां दूर कर उन्हें विकास के सफल उपक्रम बनने में सहायता देने के लिए मुख्य रूप से लघु उद्योग भारती की स्थापना की गई है। यह भारतीय गांवों को स्वावलंबन की और ले जाने का आरएसएस का महत्वपूर्ण कदम है।

1979 में स्थापित संघ का सेवा भारती प्रकल्प मुख्यत: - आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है। शिक्षा, संस्कार, स्वरोजगार और मतांतरण से रक्षा आदि इसके प्रमुख कार्य हैं।

इसंके अलावा ग्रामीण जीवन मे लोगों के रहन सहन और स्वस्थ रहने के तरीके बताने के लिए इसका गठन किया गया। आप बीमार ही न हो, इसके लिए यह संगठन काम कर रही है। ललित कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से संस्कार भारती स्थापना वर्ष 1981 में लखनऊ में की गई।

11. निष्कर्ष (Conclusion)

भारत का ग्रामीण समाज परंपरागत रूप से एक जटिल सामाजिक संरचना पर आधारित रहा है, जिसमें जाति, वर्ग, लिंग और परंपराएं सामाजिक संबंधों की दिशा और स्वरूप को निर्धारित करती रही हैं (Srinivas, 1962)। इस शोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ग्रामीण भारत में उपस्थिति और उसकी सामाजिक भूमिका का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। आरएसएस केवल एक सांस्कृतिक संगठन नहीं, बल्कि एक व्यापक वैचारिक आंदोलन और सामाजिक परियोजना के रूप में सामने आता है, जो ग्रामीण समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को पुनः परिभाषित करने का प्रयास करता है। इसकी गतिविधियाँ–जैसे शाखाओं के माध्यम से विचारों का प्रसार, सेवा कार्यों के माध्यम से सामाजिक स्वीकृति और सामाजिक समरसता के नाम पर जातिगत संबंधों में हस्तक्षेप– इस प्रयास के प्रमुख उपकरण हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, आरएसएस की भूमिका को संरचनात्मक-कार्यात्मक सिद्धांत (Parsons, 1951) के आलोक में देखा जाए तो यह संगठन ग्रामीण समाज में नैतिक अनुशासन, सामाजिक एकता और सामूहिक उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करता है। परंतु, संघर्ष सिद्धांत (Dahrendorf, 1959) के संदर्भ में इसकी भूमिका कहीं अधिक जटिल हो जाती है। आरएसएस का जातिगत संबंधों में हस्तक्षेप, वंचित वर्गों को संगठित करना और नए सामाजिक गठबंधन बनाना, पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने का कार्य करता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह संगठन एक ओर स्थायित्व की भूमिका निभाता है, तो दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन और पुनर्गठन की दिशा में भी कार्य करता है।

एंटोनियो ग्राम्शी के सांस्कृतिक आधिपत्य सिद्धांत (Gramsci, 1971) की दृष्टि से देखा जाए तो आरएसएस ग्रामीण समाज में एक वैकल्पिक सांस्कृतिक नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। शाखाओं, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रवादी आयोजनों के माध्यम से यह लोगों के सोचने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। यह सांस्कृतिक नेतृत्व केवल विचारधारा के स्तर पर सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानीय परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं के साथ घुलमिलकर एक नई सामाजिक चेतना का निर्माण करता है। इसी क्रम में विनायक सावरकर के 'हिंदुत्व' के सिद्धांत (Savarkar, 1923) और जाफरलो द्वारा व्याख्यायित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Jaffrelot, 1996) की अवधारणाएं आरएसएस

की ग्रामीण रणनीति की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, जहाँ राष्ट्र की परिकल्पना धार्मिक-सांस्कृतिक एकता पर आधारित होती है।

आरएसएस की कार्यपद्धति–विशेषकर उसका "समूह दृष्टिकोण" (cluster-based approach)–ग्रामीण भारत में सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है, जिससे योजनाएँ अधिक प्रासंगिक और प्रभावी सिद्ध होती हैं। इससे जुड़े संगठनों जैसे दीनदयाल शोध संस्थान, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय किसान संघ आदि के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, जैविक खेती, महिला सशक्तिकरण, कुटीर उद्योग, जल संरक्षण और भूमि सुधार जैसे क्षेत्रों में व्यापक और व्यावहारिक बदलाव लाए गए हैं। यह विविध कार्य ग्रामीण समाज में न केवल जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, बल्कि नए सामाजिक व्यवहार और भूमिका संबंधी संरचनाएं भी निर्मित करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के "संस्कृतिकरण" (Sanskritization) के सिद्धांत के संदर्भ में, आरएसएस द्वारा दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं को अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करना सामाजिक गतिशीलता और चेतना की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है।

इस शोध के निष्कर्षस्वरूप यह स्पष्ट होता है कि आरएसएस का प्रभाव केवल वैचारिक या धार्मिक स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि वह ग्रामीण समाज के सामाजिक ढांचे में स्थायी और गहरे परिवर्तन ला रहा है। यह परिवर्तन कभी सामाजिक समरसता के रूप में, तो कभी वर्चस्व के नए प्रारूपों के रूप में सामने आता है। इसके द्वारा विकसित की गई "स्वदेशी परियोजनाएं" और "मूक सामाजिक सहभागिता" की कार्यप्रणाली ने ग्रामीण भारत के लाखों लोगों के जीवन में धीरे-धीरे किंतु स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी है। इस प्रकार, आरएसएस को एक सांस्कृतिक संगठन के बजाय एक वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था गढ़ने वाले शक्तिशाली सामाजिक यंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए, जो परंपरा और परिवर्तन दोनों के मध्य पुल का कार्य करता है।

संदर्भ:

1. एंडरसन, वॉल्टर एवं डामले, श्रीधर (1987)। *द ब्रदरहुड इन सेफरन: द आरएसएस एंड हिंदू रिवाइवलिज़्म*। नई दिल्ली: वीस्टलैंड।
2. एंडरसन, वॉल्टर एवं डामले, श्रीधर (2018)। *RSS: A View to the Inside*। नई दिल्ली: पेंगुइन रैंडम हाउस।
3. कटजू, मंजुला (2003)। *हिंदूज़ एंड अदर्स: द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी इन इंडिया टुडे*।
4. कुमार, राधा (1993)। *द हिस्ट्री ऑफ डूइंग*। नई दिल्ली: ज़ुबान पब्लिशिंग।
5. चारी, शेषाद्रि (2015)। *हिंदू राष्ट्र की वैचारिक यात्रा*। नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
6. दत्तोपंत ठेंगड़ी (1955, 1979)। *संघ के सामाजिक संगठनों पर विचार*।
7. दीनदयाल शोध संस्थान। *ग्राम विकास और आत्मनिर्भर भारत पर केस स्टडी और परियोजनाएं*। चित्रकूट: डी.आर.आई. प्रकाशन।
8. देसाई, ए. आर. (1969)। *ग्रामीण समाजशास्त्र*।
9. पांचजन्य। *हिंदी साप्ताहिक पत्रिका*। दिल्ली: भारत प्रकाशन।
10. भारत सरकार (2017)। *पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना - आधिकारिक विज्ञप्ति*।
11. भारतीय किसान संघ। *कृषि और ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं व दस्तावेज़*।
12. बसु, तनिका (1999)। *खाकी शॉर्ट्स एंड सैफ्रन फ्लैग्स: ए क्रिटिक ऑफ द हिंदू राइट*। हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान।

13. भागवत, मोहन (2020)। *भविष्य का भारत*। नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
14. भैय्याजी जोशी। *संघ की ग्रामीण रणनीतियों पर भाषण - कार्यकारी मंडल बैठक विवरण*।
15. मिशन, रामकृष्ण; गायत्री परिवार; इस्कॉन; पतंजलि। *भूमि सुपोषण अभियान में सहयोग से जुड़ी सामूहिक रिपोर्ट*।
16. मोहन भागवत (विविध भाषण)। *भारतीय संस्कृति, ग्रामीण भारत और राष्ट्रनिर्माण पर विचार*।
17. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (2022)। *वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट 2021-22*। नागपुर: संघ मुख्यालय प्रकाशन।
18. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (2024)। *वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट 2023-24*। नागपुर: संघ मुख्यालय प्रकाशन।
19. संघ साहित्य विभाग। *हमारा संघ - डॉ. हेडगेवार के भाषणों का संकलन*।
20. सावरकर, विनायक दामोदर (1923)। *हिंदुत्व: हू इज़ ए हिंदू?* नागपुर: वीर सावरकर प्रकाशन।
21. सेवा भारती। *सेवा कार्यों पर प्रकाशन एवं रिपोर्टें*।
22. सेन, उषा (2007)। *जेंडर एंड द हिंदू राइट*।
23. संस्कार भारती। *भारतीय ललित कला और संस्कृति पर लेख संग्रह*।
24. शारदा, रतन (2018)। *राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: एक वैचारिक आंदोलन*। मुंबई: वकिल एंड वकिल पब्लिशर्स।
25. शाह, घनश्याम (1990)। *जाति और लोकतांत्रिक राजनीति*।
26. श्रीनिवास, एम. एन. (1962)। *कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एस्सेज*। एशिया पब्लिशिंग हाउस।
27. वाइज़र, विलियम (1936)। *द हिंदू जजमानी सिस्टम*।
28. Organiser (RSS Weekly - English)। दिल्ली: भारत प्रकाशन।
29. पारसन्स, टैल्कॉट (1951)। *द सोशल सिस्टम*।
30. ग्राम्शी, एंटोनियो (1971)। *सेलेक्शन्स फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स*।
31. डाहरनडॉर्फ, राल्फ (1959)। *क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी*